

बी.सी.आर. व बार...

रेल आरक्षण...

भारत के ...

लंदन में मुख्यमंत्री का...

बिहार में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्या प्रावधान किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस गणेश राम मीना की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता हेमा तिवारी की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया था कि नारी शक्ति वंदन अभियान-2023 के तहत महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया। जिसके तहत संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गत 26 सितंबर को अदिति चौधरी बनाम बार कौंसिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में बार कौंसिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया कि वह बार कौंसिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी 33 फीसदी सीट आरक्षित रखें। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने

बी.सी.आर. को महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए 28 अगस्त को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पद पर महिला नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन बी.सी.आर. में चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पद पर कभी भी कोई महिला नियुक्त नहीं हुई। इसलिए बी.सी.आर., हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर सहित, अन्य जिला बार एसोसिएशनों में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने बार कौंसिल सहित संबंधित एसोसिएशनों से जवाब मांगा है।

रह करने की अनुमति होगी। ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा, जहां वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार, ए.आर.पी. को 60 दिन करने का फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि आरक्षण कार्य के लिए प्लानिंग में आसानी हो। 120 दिन के ए.आर.पी. में यात्री कम और दलाल ज्यादा बुकिंग करते हैं। इस दौरान अक्सर देखा गया है कि यात्री यात्रा नहीं करते हैं और टिकट रद्द करना भूल जाते हैं। इससे जरूरतमंद यात्रियों को सीटें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। सूत्रों ने कहा कि पहले ए.आर.पी. 60 दिन का ही था। इसको 120 दिन करने का फैसला 31 मई 2020 को किया गया था।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगातार इनकार करता रहा है। भारत का कहना है कि उसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने के लिए कैनडा ने यह आरोप लगाया था। भारत के पूर्व राजदूत अजय बिसारिया ने कहा कि टूटो के बदले रुख से भारत को दोनो देशों के बीच रचनात्मक संवाद बढ़ाने का अवसर मिला है। टूटो के पीछे हटने से अमेरिकन प्रभाव के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंधों की जटिलता भी पता लगती है। इस प्रकार का कैनडा और भारत पर असर पड़ेगा। पर इससे टूटो कमजोर होंगे या मजबूत यह देखा जाना बाकी है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(नैरोबैंड आर.एफ. मेश नेटवर्क विकसित करने में दुनिया की अग्रणी कंपनी), जे.सी.बी. (जे.के.स्ट्रक्चर और इंस्ट्रुमेंटल उपयोग वाले वाहन बनाती है) और जिसकी राजस्थान में मैनूफैक्चरिंग यूनिट है) और ट्रायम्फ मोटरसाइकिल (ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी) के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात शामिल है।

इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने वॉण्डरलस्ट (जे.इंग्लैंड की एक प्रमुख ट्रेवल पत्रिका और वेबसाइट है) के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात

की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, एक निवेशक रोड शो में हाल ही में स्वीकृत राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (आर.आई.पी.एस.) 2024 नीति को भी लॉन्च किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल आज शाम (लंदन समयानुसार) प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से जुड़ने और मातृभूमि के

साथ उनके संबंधों को जीवंत बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा, अनिवासी राजस्थानी समुदाय से राज्य में निवेश और नए व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना में सहायता करने का भी अनुरोध किया जाएगा।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा इंग्लैंड दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस.) शिखर अग्रवाल, उद्योग विभाग और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स (बी.आई.पी.) के आयुक्त रोहित गुप्ता और राजस्थान सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी लेकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डी.जी.पी. ने मीडिया को बताया कि घटना के बाद दो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम गठित की गई हैं। एक सैटअप स्थानीय स्तर पर अपराधिक तत्वों के लिए होने का पता लगाया तथा दूसरी एस.आई.ई.टी. इस घटना व इसके पहले हुई घटनाओं की जांच करेगी। उसके आधार पर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। एक लिकर माफिया का नाम सामने आ रहा है, जो पहले भी ऐसे कांड में लिप्त रहा है। राज्य के शराबबंदी मंत्री रत्नेश साडा ने कहा था कि क्राइम कंट्रोल एक्ट लागू कर शराब माफिया को खत्म कर देंगे।

न्यायमूर्ति संजीव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और एक साल बाद यहाँ स्थायी न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किया गया था। परंपरा है कि मौजूदा सी.जे.आई. अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं, जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है।

सी.जे.आई. चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम है। इसलिए जस्टिस खन्ना का नाम आगे बढ़ाया गया है, हालांकि, उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं।

कोटा में ...

महाराष्ट्र व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

किराए पर रह रहा था, उसी मकान में उसकी बुआ की लड़की भी रहती थी। बुधवार रात को 8.30 बजे जब वह आशुतोष को खाने के लिए बुलाने गईं, तब उसे पूरे घटनाक्रम का पता चला। इसके बाद उसने पीजी मालिक को इन्फॉर्म किया। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची। बताया गया कि छात्र तीसरी बार नीट यूजी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसने बीते साल 2023 में भी कोटा में रहकर तैयारी की थी। इस साल भी वह चार-पांच महीने पहले ही कोटा आया था। जिस पीजी में छात्र आशुतोष रहता था, उसमें सुराइड प्रिवेशन रॉड (एंट्री हेंगिंग डिवाइस) नहीं थी, जबकि जिला प्रशासन ने सभी हॉस्टल्स और पीजी संचालकों को यह डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हुए हैं।

आनन्दीबेन पटेल, जो प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक मानी जाती हैं, को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर पांच साल से ज्यादा समय हो गया। जो राज्यपाल अपने पद पर तीन साल से अधिक समय से आसीन हैं, उनमें शामिल हैं- गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तथा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। इन पदों पर भी बदलाव संभावित है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्यपालों की फेरबदल की घोषणा महाराष्ट्र एवं झारखंड के चुनाव-परिणामों की घोषणा के बाद की जायेगी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

“मौसम के जोखिमों से हमारे मेहनती किसान भाई-बहनों के हितों को सुरक्षित करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी कारगर साबित हो रही है। इसका लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है।”
— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

खुशियां मिलीं सुरक्षा साथ मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ

फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियों

- 19.67 करोड़ किसान भाई-बहनों को अब तक मिला फसल बीमा का लाभ
- ₹ 1.65 लाख करोड़ के दावों का भुगतान किसानों को किया
- 70 करोड़ से अधिक किसान आवेदन प्राप्त

देशव्यापी हेल्पलाइन 14447

आपके गाँव में होने वाले शिविर में इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करें:

- बीमा पॉलिसी, सरकारी नीतियाँ, भूमि अभिलेख एवं दावे और शिकायत निवारण
- किसानों के प्रशिक्षण हेतु फसल बीमा पाठशाला

वॉट्सएप पर हमसे जुड़ें

बीमा भागीदार: AIG, Chola MS, Future Generali, ICICI Lombard, Oriental Insurance, RILIANCE, GENERAL INSURANCE, SBI general, Universal Sompo General Insurance

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जनसेवा केंद्र | क्रांप इंश्योरेंस ऐप <https://play.google.com> | पोस्ट ऑफिस | बैंक शाखा | [f](#) [i](#) [x](#) [y](#) [in](#) @PMFBY

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें

LOVED IN 75 COUNTRIES

BAJAJ THE WORLD'S FAVOURITE INDIAN

डेरिंग वाली दिवाली

₹ 10,000* तक की बचत

*कैशबैक ऑफर अन्य पल्सर मॉडल्स पर भी उपलब्ध।
अतिरिक्त ऑफर्स [Flipkart](#) और [amazon.in](#) पर भी उपलब्ध।

DEFINITELY DARING

अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें

72198 21111 | [BAJAJ SECURE](#) | [pine labs](#) | [HDFC BANK](#) INSTANT CASHBACK UP TO ₹ 5,000 ON CREDIT CARDS*

*निगम और शर्तें लागू। *ऑफर्स केवल चुनिंदा वॉरियंट्स पर ही उपलब्ध। ऑफर 15 नवंबर 2024 तक ही है। बजज ऑटो के पास बिना पूर्व सूचना के किसी भी या सभी ऑफर्स को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। मॉडल पर निर्भर करते हुए ₹ 10,000 तक की *बचत में ₹ 5000* तक का कैशबैक और ₹ 5000* एचडीएफसी कार्ड कैशबैक शामिल है। स्टॉक, एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोफेशनल सुपरवैजन के तहत, आम जनता या आम रास्ते से हट कर नियंत्रित और बंद सीमित वातावरण में किए गए हैं। कृपया इन स्टॉक की नकल करने का प्रयास न करें और हर समय ट्रेडिक तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें। एनएसी विशेष मॉडल और विशेष राज्यों में ही उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए बजज डीलर से संपर्क करें। रोड साइड सहायता अन्य पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और वह उनके नियम और शर्तों के अधीन होती है। कैशबैक ऑफर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स के ईएमआई ट्रांजेक्शन्स पर केवल पाइन लेव्स मशीन्स पर ही 15 अक्टूबर 2024 तक उपलब्ध है। ई-वॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑफर्स उनके नियम और शर्तों के अधीन हैं।

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: CHARBHUJA BAJAJ 9649820087 • Kishanghar: PAWANSHI BAJAJ 9829046068 • Beawar SHREE GANPATI BAJAJ 7976122011 • Nagaur RATHI BAJAJ 9414118589 • Bhiwar: SANDEEP BAJAJ 9413314425. Authorised Service Centre: • Arain 9929599508 • Kerkri 9214035008 • Roopangarh 9664462215 • Masuda 9928109800 • Bandhanwara 7976586550 • Kishanwar 9413169119 • Degana 9511573034 • Gotan 9414118554 • Kuchera 9887656574 • Merta City 9414118016 • Kuchaman 9414433165 • Sarwar 9636912566 • Kotri 9829300595 • Mandal 9828360242 • Mandalgarh 9414686446 • Gangapur 9783859809 • Bijoliya 949696887 • Asind 9413357319 • Raika 9414122400 • Gulabpura 9214599362 • Shahpura 9214583170 • Paroli 9983550076 • Pander 7976144602.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एच.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, उन्नयति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्यद मैन् रोड आर्यद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908